(ख) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध इस तरह के मामले सी. ई० जी. एल टी. उच्च न्यायालयों अथवा उच्चतम न्यायालय के समक्ष 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस धनराशि को शीघ्र वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा "टर्न एराउंड योजना" को प्राप्त किया जाना

1056. **श्री आस मोहम्मद** :क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को एच० ई० सी० की टर्न एराउंड योजना प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त बैंक द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) द्वारा प्रचालन एजेंसी (ओ ए) के रूप में नियुक्त भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) ने सूचित किया है कि उसे हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (एच ई सी) से संशोधित टर्न-एराउंड योजना प्राप्त हुई है । बाइफर ने एच ई सी के मामले की आखिरी बार 7 मार्च, 1995 को उस समय सुनवाई की थी जब ओ ए ने अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया कि पुनर्वास की लागत को पूरा करने के लिए कंपनी ने अपेक्षित वित्तीय राशि एकत्र नहीं की थी । बाइफर ने बोर्ड /ओ.ए. के पास संशोधित पुनरुद्धार प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए उद्योग मंत्रालय को 7 अप्रैल, 1995 तक का समय मंजूर किया है ।

Wages for Bank Employees

1057 SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in the 'Indian Express' dated 9-10-94 under the caption "Wages for bank employees revised".

(b) if so, what are the details in this respect;

(c) the cost on the national exchequer for the 10 lakh bank employees;

(d) whether it is a fact that the agreement for bank employees is for a period of five years, while the Central Pay Commission is to be set up for the Central Government Employees after every 10 years;

(e) if so, the reasons therefor; and

(f) the steps taken by Government to provide equal salaries and other facilities to both Central Government employees and Public Sector Undertakings employees?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASEKHARA MURTHY): (a) Yes, Sir.

(b) The salient features of the Settlement are annexed as Statement. (*See* below).

(c) The wage revision for the workmen employees will have incremental impact of 10.5 per cent on the existing wage bill. The cost in terms of the quantum would be approximately Rs. 388 crores p.a. The cost on account of arrears has been staggered so as to even out the impact. Discussions regarding wage revision for officers are in progress.

(d) to (f) Information is being collected and, to the extent available, will be laid on the Table of the House.